

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 468/आर-915/2020/ब-1/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/05/2022

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
(बजट नियंत्रण अधिकारी)

विषय:- Proposed procedure for Release of funds Under the centrally sponsored schemes (CSS) and monitoring Utilization of the funds released- reg.

- सन्दर्भ:-
1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 539/आर-915/2020/ब-1/चार, दिनांक 18/06/2021
 2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का पत्र क्रमांक F.No.1(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक 8 मार्च 2022
 3. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 333/आर-915/2020/ब-1/चार, दिनांक 25/03/2022

-----0-----

विषयांतर्गत लेख है कि पूर्व में इस विभाग के संदर्भित पत्र-1 के द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की प्रक्रिया के सुचारु संपादन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इसी अनुक्रम में संदर्भित पत्र क्रमांक-2 व 3 आपकी ओर प्रेषित किये गये हैं। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आदि से संबंधित भुगतान/कटौती हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाये जाने का पुनः अनुरोध है-

1. केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश व समानुपातिक राज्यांश SNA Account में निर्धारित समयावधि में स्थानांतरित की जावे।
2. केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से वेतन भत्तों से संबंधित अंश के भुगतान हेतु राज्य के बजट में एक पृथक बजट लाईन खोली जावे।

3. वेतन भत्तों से संबंधित व्यय प्रथमतः राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा तथा यह व्यय संबंधित बजट शीर्ष के विरुद्ध विकलनीय होगा। वेतन का भुगतान IFMIS के माध्यम से किया जावेगा तथा विभिन्न कटौतों जैसे सामान्य भविष्य निधि, कर्मचारी समूह बीमा, आयकर आदि भी IFMIS में PAYROLL MODULE का प्रयोग करते हुये स्वतः होंगे।
4. वेतन भत्तों के भुगतान के पश्चात सकल राशि का दावा (Claim) SNA Account से दावाकृत किया जायेगा।
5. SNA द्वारा उक्त वेतन पर किये गये भुगतान को SNA खाते से विकलित करते हुये यह राशि प्रत्येक माह राज्य की संचित निधि में विभाग के प्राप्ति शीर्ष में जमा की जायेगी।
6. SNA से प्राप्त उक्त राशि को राज्य शासन द्वारा MINUS DEBIT के रूप में वर्गीकृत करते हुये व्यय में कमी के रूप में दर्शित किया जायेगा, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेतन के विरुद्ध जो भुगतान क्रमशः IFMIS से किया गया है, उसका कोई अतिरिक्त भुगतान न हो।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आईरीन सिथिया जे.पी.)

संचालक बजट एवं अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

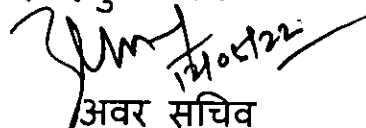
पृष्ठां. क्रमांक 469/आर-915/2020/ब-1/चार

भोपाल, दिनांक 12/05/2022

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. पर्यावास भवन, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि IFMIS में आवश्यक प्रावधान करने का कष्ट करें।
2. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य पीएफएमएस पर्यवेक्षण इकाई, म.प्र. भोपाल।
3. संचालक वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, संचालनालय संस्थागत वित्त, म.प्र. विंध्याचल भवन, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/539 /आर-915/2020/ब-1/चार

भोपाल, दिनांक 18/06/2021

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
(बजट नियंत्रण अधिकारी)

विषय:- केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की राशि विमुक्त करने एवं उनके उपयोग के अनुश्रवण की नवीन प्रक्रिया लागू किए जाने के संबंध में ।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का पत्र क्रमांक F.No.1(13)/PFMS /FCD/ 2020 दिनांक 23.03.2021 एवं पत्र दिनांक 12.04.2021(प्रति संलग्न)

-----0-----

विषयान्तर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 23.03.2021 द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की राशि विमुक्त करने एवं उनके उपयोग के अनुश्रवण की नवीन प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो 01 जुलाई 2021 से प्रभावशाली होगी।

2. वर्तमान प्रक्रिया - CSS से संबंधित राशि का आहरण एवं भुगतान कोषालयों के माध्यम से विभागीय आहरण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। कोषालयों के माध्यम से हुए व्यय का डेटा IFMIS - PFMS इंटीग्रेशन के तहत PFMS पोर्टल को प्रतिदिन शेयर किया जाता है। उक्त व्यय से संबंधित समस्त विवरण अधिकृत प्राधिकारी को अनुश्रवण हेतु PFMS पर उपलब्ध होता है।

3. नवीन निर्धारित प्रक्रिया- प्रत्येक CSS योजना के लिए (अंब्रेला योजना के संदर्भ में प्रत्येक उपयोजना के लिये) एक Single Nodal Agency(SNA) को अनुज्ञात किया जायेगा। SNA का PFMS में पंजीयन किया जावेगा। केंद्र सरकार द्वारा CSS का केंद्रांश विमुक्त करने की दिनांक से, निर्धारित समय सीमाओं में केंद्रांश एवं राज्यांश की राशि कोषालय से आहरित कर SNA के बैंक

खाते में जमा की जाएगी। उक्त खाते में जमा राशि का SNA द्वारा PFMS का उपयोग करते हुए व्यय किया जाएगा। विस्तृत प्रक्रिया संलग्न पत्रों में दी गयी है।

इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय विभाग/ SNA द्वारा निम्नांकित कार्यवाही की जाये:-

1. प्रत्येक योजना के लिए अथवा फ्लेगशिप योजना के संबंध में प्रत्येक उप योजना के लिए अलग अलग SNA अनुज्ञात किया जाये। इस हेतु प्रशासकीय विभाग की ओर से संलग्न प्रारूप 'एक' के अनुसार योजनावार पृथक-पृथक स्वीकृति जारी की जाये। विभाग की सुविधा अनुसार एक ही अधिकारी (पदनाम) को एक से अधिक योजनाओं के लिये SNA अनुज्ञात किया जा सकता है।
2. प्रत्येक योजना के SNA के पदनाम से एक बैंक खाता (अलग अलग योजना/ उपयोजना के लिये अलग अलग बैंक खाता) खोला जाये।
3. SNA एवं Implementing Agencies (IAs) के बैंक खाते उन्हीं बैंकों में खोले जायेंगे, जो म.प्र. शासन, वित्त विभाग, संस्थागत वित्त संचालनालय के आदेश क्र सअ/श.पूजी.नि/1/संविसं/2015/3240, भोपाल दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तथा आदेश क्र सअ/श.पूजी.नि/1/संविसं/2015/3296, भोपाल दिनांक 07 नवंबर 2015 अथवा इस संबंध में भविष्य में जारी किए जाने वाले आदेशों की शर्तों की पूर्ति करते हैं। SNA द्वारा बैंक का चयन करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उक्त बैंक भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.03.2021 एवं 12.04.2021 के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करते हों।
4. SNA का यह दायित्व होगा कि योजना से संबंधित सभी IAs को सूचीबद्ध किया जाये। जिस बैंक में SNA का खाता खोला गया है, उसी बैंक में सभी IAs के शून्य बैलेंस खाते खोले जायें। IAs के खाते संबंधित योजना के SNA खाते से मैप किये जायें। उक्त प्रक्रिया 25 जून, 2021 तक पूर्ण कर ली जाये। SNA द्वारा दिनांक 28 जून 2021 तक प्रगति की रिपोर्ट संलग्न प्रारूप 'दो' में कार्यालय आयुक्त, कोष एवं लेखा को प्रेषित की जाये।
5. SNA एवं IAs के उपरोक्तानुसार खाते खोलने के लिए वित्त विभाग से दिनांक 31 जुलाई, 2021 तक पृथक से कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि किसी परिस्थिति में 31 जुलाई, 2021 के पश्चात SNA / IAs के बैंक खाते खोलना आवश्यक हो तो प्रशासकीय विभाग इस हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करेगा।

6. IAs की आहरण सीमाएं निर्धारित करने एवं नवीन फंड फ्लो प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वयन के लिए SNA स्तर से प्रक्रिया निर्धारित की जाये।
7. यदि किसी योजना के लिए पूर्व में कोई बैंक खाता खोला गया है तथा वह खाता नवीन निर्देशों एवं PFMS प्रक्रिया का पालन पूर्णतः करता है, तभी उस खाते को निरंतर रखा जा सकता है।
8. भारत सरकार के संदर्भित पत्र F.No.1(13)/PFMS/FCD/ 2020 दिनांक 23.03.2021 के बिंदु क्र 13 के अनुसार यदि किसी CSS के लिये पूर्व से कोई खाता/खाते खुले हुए हैं (राज्य स्तर/जिला स्तर/अन्य कोई भी खाता) तो विभाग CSS के लिए Single Nodal Account खोलने के पश्चात् ऐसे खातों की अव्ययित राशि सम्बंधित Single Nodal Account में 1 जुलाई 2021 तक ट्रान्सफर की जाये तथा ऐसे समस्त बैंक खातों को बंद कर दिया जाये।
9. SNA की मैपिंग सम्बन्धी जानकारी संबंधित SNA द्वारा संलग्न प्रारूप 'तीन' में दिनांक 1 जुलाई, 2021 तक एवं तत्पश्चात प्रत्येक माह की 10 तारीख को आयुक्त, कोष एवं लेखा को प्रेषित की जाये।
10. भारत सरकार के संदर्भित पत्र F.No.1(13)/PFMS/FCD/ 2020 दिनांक 12.04.2021 के बिंदु क्र 2(ix) अनुसार यदि कोई केंद्र प्रवर्तित योजना पृथक केन्द्रीय या राज्य आईटी प्रणाली से क्रियान्वित की जा रही है तो उसे PFMS के साथ एकीकृत किया जाना है विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
11. भारत सरकार के संदर्भित पत्र F.No.1(13)/PFMS/FCD/ 2020 दिनांक 12.04.2021 के बिंदु क्र 2(viii) अनुसार केंद्र प्रवर्तित योजना के लिए केंद्रांश एवं राज्यांश के लिए पृथक-पृथक बजट लाइन्स खोले जाने की आवश्यकता है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी।
12. PFMS के उपयोग के सम्बन्ध में तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण राज्य स्तर पर उपलब्ध राज्य पीएफएमएस अनुश्रवण इकाई (SPMU) द्वारा दिया जाना है। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण SPMU द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार/विभाग के अनुरोध पर तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण SPMU द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
13. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उक्त कार्य निर्धारित समयसीमा 01.07.2021 के पूर्व किया जाना है, अतः इस सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाहियां निर्धारित समयसीमा में पूरी कर ली जायें। उक्त कार्यवाही के लिए निम्नांकित समय सीमाओं का पालन सुनिश्चित किया जावे-

- क. SPMU द्वारा प्रशिक्षण - 21 जून 2021
प्रातः 11.30 बजे
- ख. विभाग द्वारा SNA अनुज्ञात करने के लिए आदेश जारी करना - 22 जून 2021
- ग. बैंक चयन एवं SNA द्वारा बैंक खाता खोलना - 25 जून 2021
- घ. IAs का बैंक खाता खोलना - 27 जून 2021
- ड. SNA द्वारा प्रारूप 'दो' में SNA एवं IAs की जानकारी से आयुक्त, कोष एवं लेखा को अवगत कराना - 28 जून 2021
- च. पूर्व खातों (जो SNA के बैंक खातों के रूप में अनुज्ञात नहीं किये गए हैं) / IAs के खातों से राशि की SNA के अधिकृत खातों में वापसी तथा ऐसे समस्त खातों को बंद किया जाना - 1 जुलाई 2021
- छ. SNA द्वारा प्रारूप- तीन में जानकारी आयुक्त, कोष एवं लेखा को प्रेषित करना - 1 जुलाई 2021
तथा तत्पश्चात प्रत्येक माह की 10 तारीख
14. कृपया निर्धारित प्रक्रिया / निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)

संचालक बजट

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 18/06/2021

पृष्ठांकन क्रमांक/540 /आर-915/2020/ब-1/चार

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. पर्यावास भवन, भोपाल
2. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य पीएफएमएस पर्यवेक्षण इकाई, म.प्र. भोपाल
3. संचालक वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, मंत्रालय भोपाल
4. आयुक्त, संचालनालय संस्थागत वित्त, म.प्र. विंध्याचल भवन, भोपाल

की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार गुप्ता)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रशासकीय विभाग की ओर से SNA अनुज्ञात किए जाने हेतु आदेश का प्रारूप

मध्य प्रदेश शासन

..... विभाग

मंत्रालय,,

प्रति

SNA का पदनाम

विभाग का नाम

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र क्रमांक F.No.1(13)/PFMS /FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के (CSS) फंड विमुक्त करने एवं उनके उपयोग के अनुश्रवण की नवीन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/ /आर-915/2020/ब-1/चार, भोपाल, दिनांक /06/2021 द्वारा अनुगामी निर्देश जारी किए गये हैं। नवीन प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक CSS योजना के लिए/ अंब्रेला योजना के संदर्भ में प्रत्येक उपयोजना के लिये एक Single Nodal Agency (SNA) को अनुज्ञात किया जायेगा। उक्त निर्देशों के परिपालन में आपको निम्न अनुसार योजना एवं उप-योजना के लिए SNA अनुज्ञात किया जाता है।

क्र	योजना का नाम	उपयोजना का नाम (यदि उपलब्ध हो तो)	भारत शासन द्वारा आवंटित स्कीम कोड एवं नाम	राज्य शासन के बजट पुस्तिका में आवंटित स्कीम कोड एवं नाम

आपके द्वारा निम्नांकित कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण की जाये-

1. SNA एवं IAs के बैंक खाते उन्हीं बैंकों में खोले जायेंगे, जो म.प्र. शासन, वित्त विभाग, संस्थागत वित्त संचालनालय के आदेश क्र सअ/श.पूजी.नि/1/संविसं/2015/3240, भोपाल दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तथा आदेश क्र सअ/श.पूजी.नि/1/संविसं/2015/3296, भोपाल दिनांक 07 नवंबर 2015 अथवा इस संबंध में भविष्य में जारी किए जाने वाले आदेशों की शर्तों की पूर्ति करते हैं। SNA द्वारा बैंक का चयन करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उक्त बैंक

भारत सरकार के आदेश दिनांक 23.03.2021 तथा 12.04.2021 के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करते हों।

2. चयनित बैंक में SNA का बैंक खाता भारत शासन के पत्र क्रमांक F.No.1(13)/PFMS /FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 के अनुसार खोला जाये।
3. Implementing Agencies (IAs) को सूचीबद्ध कर, जिस बैंक में SNA खाता खोला गया है, उसी बैंक में IAs के शून्य बैलेंस खाते खोले जावें। IAs के खाते SNA खाते से मैपड रहेंगे।
4. खातों के खोलने एवं संचालन के लिए वित्तीय नियमों/निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाये।
5. उक्त कार्यवाही 27.06.2021 तक पूर्ण कर 28.06.2021 तक निर्धारित संलग्न प्रारूप 'दो' में प्रगति रिपोर्ट आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा राज्य नोडल अधिकारी, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तथा भारत शासन के संबंधित विभाग को दी जाये।
6. स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से संपर्क कर PFMS में SNAs एवं IAs को पंजीबद्ध करावें एवं खातों की मैपिंग करावें।

प्रमुख सचिव/ सचिव/ उप सचिव

-----विभाग

प्रतिलिपि

1., मंत्रालय, भारत शासन की ओर सूचनार्थ।
2. (भारत शासन के संबंधित विभागीय अधिकारी) की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित विभागाध्यक्षकी ओर प्रेषित कर लेख है कि SNA से कार्यवाही पूर्ण करावें एवं संलग्न प्रारूप 'तीन' में आयुक्त कोष एवं लेखा को जानकारी 28.06.2021 तक प्रेषित करें।
4. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, पर्यावास भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य पी.एफ.एम.एस. अनुश्रवण इकाई, म.प्र. भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त पंजीकृत किये गए SNAs/IAs की जानकारी यूनिक एजेंसी कोड, बैंक आईएफएससी कोड तथा खाता क्रमांक के विवरण सहित कार्यालय आयुक्त, कोष एवं लेखा को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराये।

कार्यालय SNA _____

विभाग _____

SNA के अधीन IAs की मैपिंग तथा बैंक खातों की जानकारी

क्र	CSS योजना का नाम	भारत शासन द्वारा आवंटित स्कीम कोड	राज्य शासन की बजट पुस्तिका में आवंटित स्कीम कोड एवं योजना का नाम	SNA का पदनाम	SNA के बैंक खाते का विवरण		SNA के अंतर्गत IAs का विवरण		
					IFSC Code	खाता क्रमांक	कुल चिन्हित IAs की संख्या	कुल IAs, जिनके बैंक खाते खोले गए	PFMS में पंजीकृत IAs खातों की संख्या

..... SNA

..... विभाग

प्रतिलिपि

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,-----विभाग
2. संबंधित विभागाध्यक्षकी ओर प्रेषित कर लेख है कि SNA से कार्यवाही पूर्ण करावें एवं संलग्न प्रारूप 'तीन' में आयुक्त कोष एवं लेखा को जानकारी 28.06.2021 तक प्रेषित करें।
3. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, पर्यावास भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य पी.एफ.एम.एस. अनुश्रवण इकाई, म.प्र. भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त पंजीकृत किये गए SNAs/IAs की जानकारी यूनिक एजेंसी कोड, बैंक आईएफएससी कोड तथा खाता क्रमांक के विवरण सहित कार्यालय आयुक्त, कोष एवं लेखा को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराये।

कार्यालय SNA _____

विभाग _____

Status of completion of preparatory activities to implement the new procedure for release of funds under CSS to the states w.e.f. 1st July, 2021

Name of the state _____

Date of Report _____

Sr no.	Name of CSS	Name of the SNA designated for the scheme	Whether the Single Nodal Account of SNA opened and mapped in PFMS	Whether the zero-based accounts of the IAs down the ladder opened	Whether all IAs have deposited 100% of the amount balance in their account to the account of SNA	Number of IAs registered in of CSS PFMS for the CSS	Whether separate budget line for Central and State share of CSS opened	Whether all bank accounts of SNA / IAs relating to this scheme, other than the single Nodal Account / Zero balance account. have been closed
1	2	3	4	5	6	7	8	9

..... SNA

..... विभाग

प्रतिलिपि

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,-----विभाग
2. संबंधित विभागाध्यक्षकी ओर प्रेषित कर लेख है कि SNA से कार्यवाही पूर्ण करावे एवं संलग्न प्रारूप 'तीन' में आयुक्त कोष एवं लेखा को जानकारी 28.06.2021 तक प्रेषित करें।
3. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, पर्यावास भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य पी.एफ.एम.एस. अनुश्रवण इकाई, म.प्र. भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त पंजीकृत किये गए SNAs/IAs की जानकारी यूनिक एजेंसी कोड, बैंक आईएफएससी कोड तथा खाता क्रमांक के विवरण सहित कार्यालय आयुक्त, कोष एवं लेखा को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराये।

F. No. 1(13)PFMS/ECD/2020
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

Block No. 11, 5th Floor,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi, dated 23/03/2021

To

Chief Secretaries/Principal Secretaries (Finance) All States/UTs

Subject: Procedure for release of funds under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) and monitoring utilization of the funds released

Sir/Madam

The General Financial Rule 232(v) prescribes the release of funds to the State Governments and monitoring utilization of funds through PFMS. For better monitoring of availability and utilization of funds released to the States under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) and to reduce float, the Department of Expenditure vide letter of even number dated 16/12/2020 had shared a draft modified procedure for release of funds under CSS with all the State governments and Ministries/Departments of the Government of India to seek their comments. The comments received from the State governments and Ministries/Departments of the Government of India were considered and the procedure has been suitably modified.

With a view to have more effective cash management and bring more efficiency in the public expenditure management, it has been decided that the following procedure will be followed by all the State Governments and Ministries/Departments of the Government of India regarding release and monitoring utilization of funds under CSS with effect from 1st July, 2021.

1. Every State Government will designate a Single Nodal Agency (SNA) for implementing each CSS. The SNA will open a Single Nodal Account for each CSS at the State level in a Scheduled Commercial Bank authorized to conduct government business by the State Government.
2. In case of Umbrella schemes which have multiple sub-schemes, if needed, the State Governments may designate separate SNAs for sub-schemes of the Umbrella Scheme with separate Single Nodal Accounts.
3. Implementing Agencies (IAs) down the ladder should use the SNA's account with clearly defined drawing limits set for that account. However, depending on operational requirements, zero balance subsidiary accounts for each scheme may also be opened for the IAs either in the same branch of the selected bank or in different branches.
4. All zero balance subsidiary accounts will have allocated drawing limits to be decided by the SNA concerned from time to time and will draw on real time basis from the Single Nodal Account of the scheme as and when payments are to be made to beneficiaries, vendors etc. The available drawing limit will get reduced by the extent of utilization.

[Handwritten Signature]

5. For seamless management of funds, the main account and all zero balance subsidiary accounts should preferably be maintained with the same bank. However, State Government may choose different banks for opening Single Nodal Accounts of different CSS.
6. Only banks having a robust IT Systems and extensive branch network should be chosen for opening the Single Nodal Account of each CSS. The bank chosen should have the facility to open the required number of subsidiary zero balance accounts and a robust MIS for handling accounting and reconciliation at each level. The bank should also provide a user friendly dashboard to officers at various levels to monitor utilization of funds by IAs.
7. The bank's software system should be able to monitor the drawing limits of the IAs who should be able to draw funds on real time basis from the SNA's account as and when payments are to be made. The selected bank should ensure proper training and capacity building of branch managers and other staff for smooth operation of these accounts.
8. The Ministries/Departments will release the central share for each CSS to the State Government's Account held in the Reserve Bank of India (RBI) for further release to the SNA's Account.
9. Funds will be released to the States strictly on the basis of balance funds of the CSS (Central and State share) available in the State treasury and bank account of the SNA as per PFMS or scheme-specific portals fully integrated with PFMS in consonance with rule 232(V) of the General Financial Rules, 2017.
10. The SNAs shall ensure that the interest earned from the funds released should be mandatorily remitted to the respective Consolidated Funds on pro-rata basis in terms of Rule 230(8) of GFR, 2017. Interest earned should be clearly and separately depicted in PFMS, scheme-specific portals integrated with PFMS and in MIS provided by the banks.
11. Except in case of schemes/sub-schemes having no State share, States will maintain separate budget lines for Central and State Share under each CSS in their Detailed Demand for Grants (DDG), and make necessary provision of the State share in the State's budget. While releasing funds to SNA, State's Integrated Financial Management Information System (IFMIS) should provide these budget heads and the same should be captured in PFMS through treasury integration.
12. In the beginning of a financial year, the Ministries/Departments will release not more than 25% of the amount earmarked for a State for a CSS for the financial year. Additional central share (not more than 25% at a time) will be released upon transfer of the stipulated State share to the Single Nodal Account and utilization of at least 75% of the funds released earlier (both Central and State share) and compliance of the conditions of previous sanction. However, this provision will not be applicable in case of schemes where a different quantum of release has been approved by the Cabinet.
13. After opening of Single Nodal Account of the scheme and before opening zero balance subsidiary account of IAs or assigning them drawing rights from SNA's account, the IAs at all levels shall return all unspent amounts lying in their accounts to the Single Nodal Account of the SNA. It will be the responsibility of the State government concerned to ensure that the entire unspent amount is returned by all the IAs to the Single Nodal Account of the SNA concerned. For this, the State Governments will work out the modalities and the timelines and will work out Central and state share in the amount so available with IAs.



SNA's will keep a record of unspent balance lying in the account of IAs and the amount refunded by IAs.

14. Refund of balance amount by IAs and the amount available in the SNA's account should be taken into account by the Program Division of the Ministry/Department while releasing funds under the scheme. Concerned SNA's shall keep a record of the unspent amount lying in the account of IAs to be deposited in the Single Nodal Account while assigning drawing rights to IAs.

15. Ministries/ Departments will ensure that releases under all CSS are made strictly as per the actual requirement on the ground, without resulting in any material float with the implementing agencies at any level.

16. The State Government will transfer the Central share received in its account in the RBI to the concerned SNA's account within a period of 21 days of its receipt. The Central share shall not be diverted to the Personal Deposit (PD) account or any other account by the State Government. Corresponding State share should be released as early as possible and not later than 40 days of release of the Central share. The funds will be maintained by the SNA in the Single Nodal Account of each CSS. State Governments/SNA's/IAs shall not transfer scheme-related funds to any other bank account, except for actual payments under the Scheme.

17. State Governments will register the SNA's and all IAs on PFMS and use the unique PFMS ID assigned to the SNA and IAs for all payments to them. Bank accounts of the SNA's, IAs, vendors and other organizations receiving funds will also be mapped in PFMS.

18. Payments will be made from the zero balance subsidiary accounts up to the drawing limit assigned to such accounts from time to time. Transactions in each Subsidiary Account will be settled with the Single Nodal Account daily through the core banking solution (CBS) on the basis of payments made during the day.

19. SNA's and IAs will mandatorily use the EAT module of PFMS or integrate their systems with the PFMS to ensure that information on PFMS is updated by each IA at least once every day.

20. SNA's will keep all the funds received in the Single Nodal Account only and shall not divert the same to Fixed Deposits/Flexi-Account/Multi-Option Deposit Account/Corporate Liquid Term Deposit (CLTD) Account etc.

21. The State IFMIS should be able to capture scheme component-wise expenditure along with PFMS Scheme Code and Unique Code of the Agencies incurring the expenditure. State Governments will ensure daily uploading/sharing of data by the State IFMIS/Treasury applications on PFMS. PFMS will act as a facilitator for payment tracking and monitoring of fund flow.

22. Release of funds by the Ministries/Departments to States towards the end of the financial year should be avoided to prevent accumulation of unspent balances with States. Ministries/Departments will arrange to complete the release well in-time so that States have ample time to seek supplementary appropriations from their respective legislatures, if required, and account for all the releases in the same financial year.

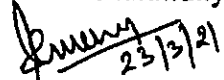
23. In case of CSS having no State share and where as per the scheme guidelines, funds are released by the Central Ministry/Department directly to the districts/blocks/Gram

Panchayats/Implementing agencies, the requirement of notifying a single Nodal Agency and opening of a Single Nodal Account at the State level may be waived by the Secretary of the Central Ministry/Department concerned in consultation with the Financial Adviser.

24. UTs without legislature work directly in PFMS. Therefore, there is no need for them to open a Single Nodal Account. They will ensure that the funds are released to the vendors/beneficiaries 'just in time'. In case funds are to be released to any agency as per scheme guidelines, provision of Rule 230 (vii) of GRF 2017 will be strictly followed to avoid parking of funds, with agencies.
25. Ministries/Departments shall undertake monthly review of the release of funds (both the Central and State Share) from the State treasury to the SNA, utilization of funds by SNAs and IAs and outputs/outcomes vis-à-vis the targets for each CSS.

This issues with the approval of Secretary (Expenditure) and shall supersede all earlier guidelines on this subject.

Yours faithfully


23/3/21

(Subhash Chandra Meena)

Director (FCD)

011-24368543

E-mail: subhash.meena@nic.in

Copy for information to:

1. PSO to Secretary (Expenditure)
2. PPS to CGA
3. Sr.PPS to Addl. Secretary (Expenditure)
4. PSO to Addl. Secretary (Pers)
5. Sr. PPS to JS (PFC-II)
6. Sr. PPS to JS(PF-S)

14/3/22

Gen-Co/1587
Date 09/3/2022

F. No 1(13)/PFMS/FCD/2020
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग (ब-1)
ब.क्र. 1/अ. 290 / चार/ब-1
दिनांक 14/03/22

5th Floor, Block 11, CGO Complex
New Delhi, the 8th March, 2022

To

1. All Chief Secretaries/Principal Secretaries (Finance) of all States/UTs.
2. All State Directorates of PFMS.

Subject: Procedure for release of funds under the Centrally Sponsored Scheme (CSS) and monitoring utilization of the funds released - reg

I am directed to refer to this Department's letter of even number dated 23rd March, 2021 on the above mentioned subject. Taking into consideration of the issues raised by various State Governments regarding processing of handling salaries, remittance of statutory dues and other deductions of employees engaged in implementation of CSS such as Samagra Siksha, ICDS etc., it has been decided that the following procedure may be adopted regarding payment of salaries, remittance of statutory dues and other deductions of employees engaged in implementation of CSS:

- i. Entire Gov releases along with the State's share for CSS will be transferred to the Single Nodal Account (SN Account).
- ii. A separate budget line for the salary portion of such employees will be created in the State budget.
- iii. The expenditure towards salary of such officers will be initially borne by the State Govt. and booked under these heads. The record of deductions from their salary such as GPF, GIS, ITAX etc. will be maintained in HRMS/IFMIS of the State.
- iv. After the disbursement of salaries, a claim for the gross amount will be raised with the SNA.
- v. SNA will book the expenditure under salary component and remits the amount claimed to the treasury.
- vi. The amount received from the SNA, will be classified as reduction of expenditure (minus debit) setting off the expenditure initially booked against salary to ensure that the above expenditure will not entail any additional cash outgo for the State.

This issues with the approval of Finance Secretary and Secretary (Expenditure).

Signature of Abhay Kumar
(Abhay Kumar)
Director
Tel. No. 24360647
Dr. (B-1)

Copy to: Secretaries to Government of India (As per list attached)

S(AK) + CTR + DIR (B)
(separate copies)

16 MAR 2022

We may issue to (from B-1)

Div (B-1)
1. A letter should be issued to all Depts. will also have the arrangements.

1401/P5FMS

No. 1587
Dir. Budget
Date 09/03/2022
Out

855/13/AC/m
14/3/22

PS (Finance)
9.3.22

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक ६३३/आर-915/2020/ब-1/चार

भोपाल, दिनांक २६/03/2022

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
(बजट नियंत्रण अधिकारी)

विषय:- Proposed procedure for Release of funds Under the centrally sponsored schemes (CSS) and monitoring Utilization of the funds released- reg.

- सन्दर्भ:-
1. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का पत्र क्रमांक F.No.1(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक 8 मार्च 2022
 2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 539/आर-915/2020/ब-1/चार, दिनांक 18/06/2021

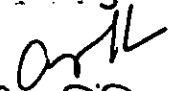
-----0-----

विषयांतर्गत लेख है कि पूर्व में इस विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की प्रक्रिया के सुचारु संपादन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,


(आईरीन सिथिया जे.पी.)

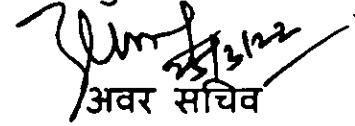
संचालक बजट

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. पर्यावास भवन, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि IFMIS में आवश्यक प्रावधान करने का कष्ट करें।
2. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य पीएफएमएस पर्यवेक्षण इकाई, म.प्र. भोपाल।
3. संचालक वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, संचालनालय संस्थागत वित्त, म.प्र. विंध्याचल भवन, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग